



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1725]

No. 1725]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 11, 2008/अग्रहायण 20, 1930

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 11, 2008/AGRAHAYANA 20, 1930

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2008

का.आ. 2860(अ).—विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मेघालय के हन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउन्सिल (एचएनएलसी) को विधि-विरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, एतद्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश सुश्री न्यायमूर्ति रेखा शर्मा की अध्यक्षता में एक “विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण” का गठन करती है।

[फा. सं. 11011/53/2008-एन.ई.-III]

ए. के. गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2008

S.O. 2860(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes “The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal” consisting of Ms Justice Rekha Sharma, Judge of Delhi High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause of declaring the Hynniewtre National Liberation Council (HNLC) of Meghalaya as Unlawful Association.

[F. No. 11011/53/2008-NE.-III]

A.K. GOYAL, Jt. Secy.